विचार बिन्दु

संसार में सबसे बड़ा अधिकार सेवा और त्याग से प्राप्त होता है। –प्रेमचंद

स्टार्टअप्स से संवरेगा राजस्थान

राजस्थान अब केवल किलों, मेलों, रेगिस्तान और परंपराओं का प्रदेश नहीं रह गया है। यह प्रदेश नए विचारों, तकनीक, उद्यिमता और रोजगार सृजन के एक उभरते केंद्र के रूप में भी पहचान बना रहा है। देश के अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान के पास युवा जनसंख्या, विविध उद्योगों की संभावना, सस्ती भूमि, सांस्कृतिक विरासत, पर्यटन, खनिज, कृषि, हस्तशिल्प और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों की प्रचुर संभावनाएँ हैं। यदि इन संसाधनों को आधुनिक तकनीक, नवाचार और स्टार्टअप संस्कृति से जोड़ा जाए, तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था को नई गति मिल सकती है। स्टार्टअप्स केवल छोटे कारोबार नहीं होते; ये समस्याओं के समाधान, रोजगार के अवसर, निवेश के आकर्षण और सामाजिक परिवर्तन के वाहक बन सकते हैं। इसीलिए कहा जा सकता है कि स्टार्टअप्स से राजस्थान का भविष्य संवरेगा।

स्टार्टअप का अर्थ केवल बडे शहरों में तकनीकी कंपनियाँ खोलना नहीं है। स्टार्टअप वह उद्यम है, जो किसी समस्या का नया, किफायती और प्रभावी समाधान खोजता है। यह एक छोटे विचार से शुरू होकर नए उत्पाद, सेवा या व्यवसाय मॉडल के रूप में विकसित हो सकता है। राजस्थान में स्टार्टअप की संभावनाएँ केवल जयपुर, उदयपुर या जोधपुर जैसे शहरों तक सीमित नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित समाधान, डेयरी प्रबंधन, जल संरक्षण, सौर ऊर्जा, हस्तशिल्प की ऑनलाइन बिक्री, पर्यटन से जुडी डिजिटल सेवाएँ, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तकनीक जैसे क्षेत्रों में अपार अवसर मौजूद हैं। यदि स्थानीय समस्याओं को समझकर उनके समाधान विकसित किए जाएँ, तो स्टार्टअप गाँव से लेकर शहर तक आर्थिक परिवर्तन ला सकते हैं।

राजस्थान की सबसे बड़ी ताकत इसकी युवा आबादी है। राज्य के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों से हर वर्ष हजारों युवा शिक्षा पूरी करते हैं। लेकिन रोजगार के अवसरों की सीमित उपलब्धता के कारण कई युवा प्रदेश छोड़कर मुंबई, बेंगलुरु, गुरुग्राम या दिल्ली जाने को विवश होते हैं। यह प्रवास राज्य के लिए प्रतिभा की हानि है। यदि राजस्थान में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत हो, तो युवाओं को अपने ही प्रदेश में रोजगार और उद्यम के अवसर मिलेंगे। एक सफल स्टार्टअप न केवल संस्थापक के लिए आजीविका का साधन बनता है, बल्कि डेवलपर, डिजाइनर, मार्केटिंग प्रोफेशनल, लेखाकार, लॉजिस्टिक्स कर्मी, ग्राहक सेवा कर्मी और कई अन्य क्षेत्रों में रोजगार पैदा करता है। इस प्रकार स्टार्टअप्स बेरोजगारी की समस्या को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

राजस्थान सरकार ने भी स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। राज्य की प्रमुख पहल 'आईस्टार्ट राजस्थान' है, जो 2017 में शुरू की गई थी। यह प्लेटफॉर्म स्टार्टअप्स को विचार से लेकर विस्तार तक विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान करता है। इसके अंतर्गत पूर्व-बीज स्तर के स्टार्टअप्स को विचार अनुदान के रूप में दो लाख चालीस हजार रुपये तक की सहायता दी जा सकती है। महिला संस्थापकों के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स, जिनमें पचास प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी महिलाओं के पास हो, को अतिरिक्त साठ हजार रुपये की सहायता भी दी जाती है। यह प्रावधान महिला उद्यिमता को प्रोत्साहित करने की दिशा में सराहनीय है।

स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ी चुनौती प्रारंभिक पूँजी होती है। अच्छा विचार होने के बावजूद कई युवा उद्यमी धन की कमी से पीछे हट जाते हैं। राजस्थान में इस समस्या के समाधान हेतु विभिन्न वित्तीय सहायता योजनाएँ चलाई जा रही हैं। व्यवहार्यता अनुदान, बीज निधि, विस्तार निधि और इक्विटी सहायता जैसे प्रावधान स्टार्टअप्स को विकास के विभिन्न चरणों में सहयोग देते हैं। वृद्धि चरण के स्टार्टअप्स को स्केल-अप फंड के माध्यम से उनके द्वारा जुटाई गई राशि के पचास प्रतिशत तक की सहायता देने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने वैकल्पिक निवेश कोष के माध्यम से इक्विटी सहायता भी उपलब्ध कराई है, जिसमें पात्र स्टार्टअप के लिए पाँच करोड़ रुपये तक की मिलान निवेश सहायता की बात कही गई है।

राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि का विशेष महत्व है। बाजरा, गेहूँ, दालें, तिलहन, मसाले, दूध उत्पाद, ऊन और बागवानी जैसे क्षेत्र राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। लेकिन किसानों को अभी भी उचित मूल्य, बाजार, भंडारण, बीज, सिंचाई, मौसम पूर्वानुमान और तकनीक की कमी से जूझना पडता है। यहीं पर कृषि स्टार्टअप्स बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। ड्रोन से फसल निरीक्षण, मिट्टी परीक्षण, सटीक सिंचाई, डिजिटल मंडी, किसानों के लिए ऋण और बीमा सेवाएँ, खाद्य प्रसंस्करण तथा सीधे उपभोक्ता तक उत्पाद पहुँचाने वाले मॉडल ग्रामीण आय बढ़ा सकते हैं। यदि राजस्थान के किसानों को तकनीक से जोड़ा जाए, तो कृषि क्षेत्र में क्रांति संभव है।

राजस्थान सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। यहाँ की धूप, रेगिस्तानी भूमि और बड़े पैमाने की भूमि उपलब्धता नवीकरणीय ऊर्जा के लिए अनुकूल है। सौर ऊर्जा, बैटरी भंडारण, ग्रीन हाइड्रोजन, ऊर्जा दक्षता, स्मार्ट ग्रिड और ग्रामीण विद्युतीकरण से जुड़े स्टार्टअप्स राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में और आगे ले जा सकते हैं। साथ ही ये स्टार्टअप्स पर्यावरण संरक्षण और रोजगार सृजन का संतुलित मॉडल प्रस्तुत कर सकते हैं। जल संकट से निपटने के लिए वर्षा जल संचयन, बूंद-बूंद सिंचाई, जल गुणवत्ता निगरानी और पुनर्चक्रित जल प्रबंधन से जुड़े उद्यम भी राजस्थान के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

पर्यटन राजस्थान की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, पुष्कर, अजमेर, माउंट आबू और रणथंभौर जैसे स्थान देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। लेकिन पर्यटन क्षेत्र को अभी भी आधुनिक तकनीक, बेहतर अनुभव और डिजिटल सुविधाओं की आवश्यकता है। स्थानीय हस्तशिल्प, खान-पान, सांस्कृतिक अनुभव और ग्रामीण पर्यटन को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने वाले स्टार्टअप्स स्थानीय लोगों की आय बढ़ा सकते हैं। होम स्टे, वर्चुअल टूर, डिजिटल गाइड, आगंतुक प्रबंधन, स्थानीय कारीगरों के उत्पादों की ई-कॉमर्स बिक्री और धार्मिक पर्यटन से जुड़ी सेवाएँ राजस्थान की पर्यटन अर्थव्यवस्था को नया आयाम दे सकती हैं।

राजस्थान की हस्तशिल्प परंपरा विश्व प्रसिद्ध है। ब्लू पॉटरी, ब्लॉक प्रिंटिंग, बंधेज, जयपुरी कालीन, आभूषण, लाख की चूड़ियाँ, लोहारकला, लकड़ी की नक्काशी और चमड़े के उत्पाद राज्य की सांस्कृतिक पहचान हैं। लेकिन कई कारीगर अपने उत्पादों का उचित मूल्य नहीं पा पाते और बिचौलियों पर निर्भर रहते हैं। स्टार्टअप्स इन कारीगरों को डिजिटल प्लेटफॉर्म, ब्रांडिंग, डिजाइन सुधार, गुणवत्ता प्रमाणन, अंतरराष्ट्रीय बाजार और सीधी बिक्री से जोड़ सकते हैं। इससे पारंपरिक कला केवल बची नहीं रहेगी, बल्कि आधुनिक बाजार में नई पहचान भी पाएगी। यह ग्रामीण महिलाओं और सीमांत वर्गों के सशक्तिकरण का भी मार्ग है।

राजस्थान सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। यहाँ की धूप, रेगिस्तानी भूमि और बड़े पैमाने की भूमि उपलब्धता नवीकरणीय ऊर्जा के लिए अनुकूल है। सौर ऊर्जा, बैटरी भंडारण, ग्रीन हाइड्रोजन, ऊर्जा दक्षता, स्मार्ट ग्रिड और ग्रामीण विद्युतीकरण से जुड़े स्टार्टअप्स राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में और आगे ले जा सकते हैं। साथ ही ये स्टार्टअप्स पर्यावरण संरक्षण और रोजगार सृजन का संतुलित मॉडल प्रस्तुत कर सकते हैं।

शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी स्टार्टअप्स राजस्थान को सशक्त बना सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विशेषज्ञ चिकित्सा सेवा तक पहुँच अभी भी चुनौती है। ऑनलाइन शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, स्थानीय भाषा में डिजिटल पाठ्यसामग्री, टेलीमेडिसिन, मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयाँ, डायग्नोस्टिक सेवाएँ और मातृ-शिशु स्वास्थ्य से जुड़े समाधान ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता सुधार सकते हैं। ऐसे स्टार्टअप्स न केवल व्यापारिक सफलता पा सकते हैं, बल्कि सामाजिक न्याय और समान अवसर की दिशा में भी योगदान देते हैं।

स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ाने के लिए केवल सरकारी योजनाएँ पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए संस्थागत परिवर्तन भी आवश्यक है। स्कूलों और कॉलेजों में उद्यमिता शिक्षा को व्यावहारिक बनाया जाना चाहिए। छात्रों को केवल नौकरी पाने के लिए तैयार नहीं, बल्कि रोजगार सृजन के लिए भी प्रेरित किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालयों में इनक्यूबेशन सेंटर, प्रोटोटाइप लैब, मेंटरशिप और उद्यम प्रतियोगिताओं को मजबूत किया जाना चाहिए। शिक्षकों और प्राध्यापकों को भी नवाचार एवं उद्यमिता के प्रति संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। राजस्थान सरकार का व्यावसायिक नवाचार कार्यक्रम भी शिक्षकों और छात्रों के उद्यमशीलता कौशल, इनक्यूबेशन अवसंरचना, डिजिटल एकीकरण और जन-जागरूकता पर केंद्रित है, जो सही दिशा में एक कदम है।

स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ उनके लिए नियामक सरलता भी आवश्यक है। पंजीकरण, लाइसेंस, जीएसटी, श्रम कानून, भूमि आवंटन और अनुमोदन प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाना चाहिए। एक-विंडो सिस्टम, ऑनलाइन अनुमोदन, पारदर्शी समय-सीमा और स्टार्टअप मित्र नीतियाँ उद्यमियों का विश्वास बढ़ाएँगी। यदि कागजी कार्यवाही में महीनों बीत जाएँ, तो छोटे स्टार्टअप की गति रुक सकती है। इसलिए सरकार को नीतिगत घोषणाओं के साथ उनके व्यावहारिक क्रियान्वयन पर भी ध्यान देना होगा।

राजस्थान में स्टार्टअप संस्कृति को ग्रामीण स्तर तक ले जाना सबसे बड़ी आवश्यकता है। जिला स्तर पर इनोवेशन हब, ब्लॉक स्तर पर उद्यमिता केंद्र और पंचायत स्तर पर डिजिटल सहायता केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं। ग्रामीण युवाओं को इंटरनेट, डिजिटल कौशल, बैंकिंग सेवाएँ और मार्केट लिंकेज उपलब्ध कराना होगा। स्थानीय समस्याओं को समझने वाले युवा ही सबसे प्रभावी समाधान विकसित कर सकते हैं। गाँव का युवा यदि कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, ऊर्जा या सेवा क्षेत्र में उद्यम शुरू करे, तो पलायन रुकेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

महिला उद्यिमता राजस्थान के विकास का एक अछूता आयाम है। राज्य की महिलाएँ सिलाई, बुनाई, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, सौंदर्य सेवाएँ, हस्तशिल्प और घरेलू उद्यम में पहले से सक्रिय हैं। इन्हें डिजिटल प्रशिक्षण, ऋण, बाजार और तकनीकी सहायता देकर बड़े उद्यमों में बदला जा सकता है। महिला संस्थापकों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने की राज्य की नीति इस दिशा में सकारात्मक संकेत है। यदि महिलाएँ आर्थिक रूप से सशक्त होंगी, तो परिवार, समाज और राज्य तीनों का विकास होगा।

स्टार्टअप्स की सफलता के लिए विफलता को भी स्वीकार करने वाला वातावरण चाहिए। हर स्टार्टअप सफल नहीं होता, लेकिन विफलता भी अनुभव और सीख है। समाज में यह धारणा बदलनी होगी कि सरकारी नौकरी ही सुरक्षित भविष्य है। परिवारों, शिक्षकों और समाज को युवाओं को जोखिम लेने, प्रयोग करने और नए विचार आजमाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। विफल उद्यमियों को फिर से शुरुआत करने के अवसर देने वाली नीतियाँ भी उपयोगी हो सकती हैं। राजस्थान के 'लर्न, अर्न एंड प्रोग्रेस' कार्यक्रम का उद्देश्य भी उन स्टार्टअप्स की सहायता करना है, जो विभिन्न कारणों से कठिनाई या बंद होने का सामना कर रहे हैं।

राजस्थान को स्टार्टअप हब बनाने के लिए जयपुर को राज्य का प्रमुख नवाचार केंद्र बनाया जा सकता है, साथ ही उदयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर जैसे शहरों में क्षेत्रीय केंद्र विकसित किए जाने चाहिए। जयपुर में सॉफ्टवेयर, डिजिटल सेवाएँ और डिजाइन; उदयपुर में पर्यटन एवं कला; जोधपुर में हस्तशिल्प एवं सौर ऊर्जा; कोटा में शिक्षा तकनीक; बीकानेर में खनिज एवं कृषि प्रसंस्करण; तथा श्रीगंगानगर में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े स्टार्टअप क्लस्टर विकसित किए जा सकते हैं। क्षेत्रीय विशेषज्ञता से राज्य की अर्थव्यवस्था अधिक संतुलित और समावेशी बनेगी।

स्टार्टअप्स राजस्थान के लिए केवल आर्थिक अवसर नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता का मार्ग हैं। जब स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय युवा करेंगे, तो विकास अधिक स्थायी होगा। जब किसान तकनीक से जुड़ेंगे, कारीगर वैश्विक बाजार तक पहुँचेंगे, महिलाएँ उद्यमी बनेंगी और युवा प्रदेश छोड़ने के बजाय नए अवसर बनाएँगे, तब राजस्थान वास्तव में नए युग में प्रवेश करेगा। सरकार, उद्योग, शिक्षण संस्थान, निवेशक और समाज को मिलकर एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाना होगा, जहाँ हर विचार को परखने, विफल होने, सीखने और फिर उठने का अवसर मिले।

अंतत: यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि स्टार्टअप्स से राजस्थान का भविष्य संवरेगा। रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों में भी जीवन को संभालने वाले राजस्थान के लोगों में संघर्ष, धैर्य और नवाचार की क्षमता पहले से मौजूद है। आज आवश्यकता है इस क्षमता को आधुनिक अवसरों से जोड़ने की। यदि राजस्थान अपने युवाओं को नौकरी माँगने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले उद्यमी बनाने की दिशा में आगे बढ़ाता है, तो आने वाले दशकों में यह प्रदेश देश के प्रमुख स्टार्टअप राज्यों में गिना जाएगा। तब राजस्थान की पहचान केवल वीरता, किलों और रंगों से नहीं, बल्कि नवाचार, तकनीक और उद्यिमता से भी होगी।

–अतिथि संपादक,
अविनाश जोशी,
वरिष्ठ पत्रकार एवं कॉरपोरेट सलाहकार

पर्यावरण का निष्कासन: प्रकृति विहीन कक्षा 10 के पाठ्यक्रम



प्रोफेसर अशोक कुमार

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 10 के पाठ्यक्रम से 'पर्यावरण अध्ययन' को हटाने का निर्णय केवल एक प्रशासनिक फेरबदल नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा नीतिगत कदम है जो भविष्य को अंधकार में धकेलने जैसा है। जिस दौर में दुनिया जलवायु संकट, बेकाबू ग्लोबल वार्मिंग, विषैली होती हवा और सूखती नदियों के अस्तित्वगत संकट से जूझ रही हो, उस दौर में भविष्य की पीढ़ी के हाथों से पर्यावरण बोध की किताब छीन लेना उचित है।

यह निर्णय यह गंभीर संदेह पैदा करता है कि क्या यह कदम अनियंत्रित औद्योगिक पूंजीवाद और बड़े कॉरपोरेट घरानों को उपकृत करने के उद्देश्य से उठाया गया है? क्या नीति-नियंताओं की मंशा यह है कि हमारे किशोर और युवा मन उस औद्योगिक तबाही, प्राकृतिक संसाधनों की खुली लूट और विनाशकारी प्रदूषण से पूरी तरह अनजान रहें, जिसकी कीमत आज समूची मानव सभ्यता चुका रही है? नीति-निर्माताओं को बिना किसी विलंब के पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि यह सवाल केवल परीक्षा के अंकों का नहीं, बल्कि हमारी भावी पीढ़ियों के अस्तित्व का है।

कक्षा 10 किसी भी विद्यार्थी के अकादमिक और बौद्धिक जीवन का वह निर्णायक मोड़ होता है, जहां से वह सामान्य अध्ययन से निकलकर विशिष्ट अनुशासनों (विज्ञान, वाणिज्य अथवा मानविकी) की ओर कदम बढ़ाता है। यही वह उम्र होती है जब किशोरों में सामाजिक दायित्व, तार्किक चिंतन और वैश्विक समस्याओं के प्रति एक स्वतंत्र दृष्टिकोण विकसित होता है।

यदि इसी महत्वपूर्ण पड़ाव पर विद्यार्थियों को पर्यावरण, पारिस्थितिकी संतुलन, जैव-विविधता और कार्बन फुटप्रिंट के बुनियादी सिद्धांतों से वंचित कर दिया जाए, तो हम समाज में केवल ऐसे रोबोट तैयार करेंगे जो उत्पादन और उपभोग की अंतहीन अंधी दौड़ में दौड़ने के लिए तो प्रशिक्षित होंगे, लेकिन जिनमें उस धरती के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं होगी जिस पर वे सांस लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन कोई सजावटी या अतिरिक्त विषय नहीं है; यह जीवन जीने का बुनियादी विज्ञान है। इसे मुख्य पाठ्यक्रम से बाहर फेंकना शिक्षा की मूल आत्मा पर ही गहरा प्रहार है।

यह सवाल उठाना सर्वथा स्वाभाविक और प्रासंगिक है कि आख़िर इस निर्णय के पीछे अदृश्य दबाव किसका है? आज का बेलगाम औद्योगिक पूंजीवाद प्राकृतिक संसाधनों-जल, जंगल और ज़मीन-को केवल कच्चे माल और मुनाफ़े के साधन के रूप में देखता है। फैक्ट्रियों से निकलता रासायनिक कचरा, नदियों में बहता ज़हर, जंगलों का अंधाधुंध कटान और पहाड़ों का सीना चीरकर किया जा रहा अनियंत्रित खनन-यह सब 'विकास' के उस मॉडल की देन है जो विनाश की नींव पर खड़ा है।

जब बच्चे विद्यालयों में यह पढ़ते हैं कि औद्योगिक उत्सर्जन से ओजोन परत कैसे क्षीण होती है, प्लास्टिक कचरा महासागरों को कैसे निगल रहा है, और कॉरपोरेट लालच किस तरह उपजाऊ भूमि को बंजर बना रहा है, तो उनके भीतर सवाल पूछने की चेतना जागती है। वे यह समझना शुरू करते हैं कि विकास और विनाश के बीच की सीमा रेखा कहां है।

यदि पाठ्यक्रम से इन कड़वे सत्यों को ही हटा दिया जाए, तो उद्योगपतियों के लिए पर्यावरणीय नियमों की अवहलेना करना और भी आसान हो जाएगा। एक ऐसी पीढ़ी जो पारिस्थितिकीय अपराधों के प्रति पूरी तरह निरक्षर और संवेदनहीन होगी, वह कभी कॉरपोरेट प्रदूषण पर जवाबदेही तय नहीं करेगी। क्या हमारा शिक्षा तंत्र अब स्वतंत्र नागरिक तैयार करने के बजाय कॉरपोरेट घरानों के लिए आज्ञाकारी, सवाल न पूछने वाले उपभोक्ता और श्रमिक तैयार करने की प्रयोगशाला बन चुका है? यह 'शिक्षा प्रदूषण' का सबसे बुरा रूप है, जहां पाठ्यक्रम को बाज़ार की सुविधा के अनुसार छांटा और काटा जा रहा है।

एक जीवविज्ञानी और पर्यावरण चेतना के प्रति संवेदनशील नागरिक के नाते यह देखकर स्तब्ध रह जाना पड़ता है कि जब विज्ञान हमें प्रकृति के विनाश के ख़िलाफ़ चेतावनी दे रहा है, तब हमारा शिक्षा बोर्ड आंखें मूंद रहा है। आज वैज्ञानिक शोध चीख-चीख कर कह रहे हैं कि:- वायु और जल प्रदूषण की भयावहता: भारत के अधिकांश महानगर और औद्योगिक शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में शुमार हैं। हमारे बच्चों के फेफड़े बचपन में ही धुएं और विषैले रसायनों से छलनी हो रहे हैं।

पारिस्थितिकी तंत्र का पतन: अनियंत्रित रासायनिक खादों और कीटनाशकों के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता और खाद्य श्रृंखला पूरी तरह दूषित हो चुकी है, जिसके परिणामस्वरूप कैंसर और असाध्य रोगों की महामारी फैल रही है।

जलवायु परिवर्तन की मार: असमय बाढ़, भीषण सूखा और असहनीय लू की लहरें अब कोई मौसमी विचलन नहीं, बल्कि नियमित आपदाएं बन चुकी हैं। इन जमीनी हकीकतों के बावजूद, यह सोचना कि 15-16 वर्ष के विद्यार्थियों को पर्यावरण का गहन अध्ययन कराने की आवश्यकता नहीं है, एक ऐसा शुतुरमुर्गी रवैया है जो देश को तबाही की ओर ले जाएगा। जब यूरोप और अन्य विकसित देश अपने प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक क्लाइमेट लिटरेसी (जलवायु साक्षरता) को अनिवार्य बना रहे हैं, तब भारत का सबसे बड़ा परीक्षा बोर्ड पर्यावरण अध्ययन को ही विलोपित कर रहा है। यह आधुनिकता की नहीं, बल्कि बौद्धिक दिवालियापन की निशानी है।

शिक्षा प्रदूषण का बढ़ता दायरा

अक्सर सम्मेलनों और सेमिनारों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत समठा, अंत:विषय और मूल्य-आधारित शिक्षा की बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं। परंतु नीति के धरातल पर जो फैसले लिए जा रहे हैं, वे इन दावों की पोल खोलते हैं।

यदि शिक्षा में से प्रकृति, समाज और मानवीय अस्तित्व से जुड़े विषयों को बाहर कर केवल परीक्षा-केंद्रित और बाज़ार-उन्मुख सामठी ही रखी जाएगी, तो यह शिक्षा व्यवस्था केवल उपाधियां बांटने का यंत्र बनकर रह जाएगी। शिक्षा का काम छात्र को केवल नौकरी पाने लायक बनाना नहीं है; उसका प्राथमिक दायित्व एक जिम्मेदार, संवेदनशील और जागरूक नागरिक गढ़ना है। जब छात्र यह नहीं जानेगा कि उसके आसपास का पर्यावरण कैसे काम करता है, तो वह एक जिम्मेदार वैज्ञानिक, इंजीनियर, अर्थशास्त्री या प्रशासक कैसे बन सकता है? पर्यावरण अध्ययन को हटाने का निर्णय शिक्षा के इसी नैतिक और सामाजिक उद्देश्य पर कुठाराघात करता है। यह समय चुप बैठने या औपचारिक बयानों से पल्ला झाड़ने का नहीं है। शिक्षा मंत्रालय, सीबीएसई के नीति-निर्धारकों और प्रबुद्ध समाज को इस गंभीर भूल का तुरंत संज्ञान लेना चाहिए:**-निर्णय की तत्काल वापसी:** केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अपनी इस नीति को तत्काल प्रभाव से वापस लेना चाहिए और कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में पर्यावरण अध्ययन को एक अनिवार्य, स्वतंत्र और व्यावहारिक विषय के रूप में पुनर्स्थापित करना चाहिए।

व्यावहारिक और शोध-आधारित पाठ्यक्रम: पर्यावरण अध्ययन को केवल किताबों में लिखी रटंत विद्या तक सीमित न रखकर इसे स्थानीय पारिस्थितिकी, वृक्षारोपण, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन और जैविक जीवनशैली के व्यावहारिक प्रोजेक्ट्स से जोड़ा जाए।

कॉरपोरेट हितों से शिक्षा की मुक्ति: शिक्षा नीतियों और पाठ्यक्रम निर्माण से बाज़ार और औद्योगिक दबाव समूहों के अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप को पूरी तरह समाप्त किया जाए। पाठ्यक्रम का निर्धारण शिक्षाविदों, पर्यावरण वैज्ञानिकों और समाजशास्त्रियों की स्वायत्तता से होना चाहिए, न कि किसी औद्योगिक लॉबी के इशारे पर।

सख्त मूल्यांकन प्रणाली: पर्यावरण विषय को किसी औपचारिक औपचारिकता की तरह नहीं, बल्कि छात्रों की समग्र ग्रेडिंग का एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य हिस्सा बनाया जाए, ताकि वे इसके प्रति गंभीर रहें।

धरती हमें विरासत में अपने पूर्वजों से नहीं मिली है, बल्कि यह हमने अपने बच्चों से उधार ली है। यदि हम अपने बच्चों को उस उधार की हिफाज़त करने का बुनियादी ज्ञान ही नहीं देंगे, तो आने वाला इतिहास हमारी शिक्षा नीतियों को कभी माफ नहीं करेगा। औद्योगिक पूंजीवाद के मुनाफे की हवस में यदि हमने अपनी नई पीढ़ी की पर्यावरणीय चेतना की बलि चढ़ा दी, तो यह समूची सभ्यता के आत्मदाह का मार्ग प्रशस्त करेगा। शिक्षा मंत्रालय को समय रहते जागना होगा- हमारे अस्तित्व, हमारी भावी पीढ़ियों और इस धरा के जीवन की रक्षा के लिए।

–प्रोफेसर अशोक कुमार,
पूर्व कुलपति, कानपुर एवं
गोरखपुर विश्वविद्यालय

बालिका शिक्षा में गोयदानी (मेहता) माहेश्वरी परिवार के योगदान ने इतिहास बनाया



अचलदास डांगरा

स्वर्णनगरी जैसलमेर का इतिहास केवल शौर्य, पराक्रम और स्थापत्य कला तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहां के भामाशाहों द्वारा समाजहित में किए गए त्याग, दान और जनकल्याण के कार्य भी इसकी गौरवशाली पहचान हैं। इन्हीं प्रेरणादायी प्रसंगों में गोयदानी (मेहता) माहेश्वरी परिवार का बालिका शिक्षा के क्षेत्र में योगदान एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय है, जिसने मरुभूमि में बेटियों की शिक्षा को नई दिशा प्रदान की।

जिस दौर में सीमावर्ती जैसलमेर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका शिक्षा को लेकर जागरूकता सीमित थी, उस समय बेटियों के लिए शिक्षा की मजबूत नींव रखने का प्रयास अपने आप में क्रांतिकारी कदम था। राजकीय माध्यमिक बालिका विद्यालय, सुथार पाड़ा (जैसलमेर) से शुरू हुआ यह सफर आज श्रीमती किशनी देवी मगनीराम मोहता राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में सैकड़ों बालिकाओं के सपनों को पंख दे रहा है।

जैसलमेर के सुथार पाड़ा की तंग गलियों में संचालित होने वाला राजकीय माध्यमिक बालिका विद्यालय उस समय बालिका शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। स्थानीय नागरिक आज भी इसे आत्मीयता से सुथार पाड़ा स्कूल के नाम से याद करते हैं। इस विद्यालय का इतिहास जैसलमेर में महिला शिक्षा के विकास की कहानी से जुड़ा हुआ है। सीमित संसाधनों और सामाजिक परिस्थितियों के बीच बालिकाओं को शिक्षा उपलब्ध कराने का यह प्रयास आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बना।

बाद में मोहता परिवार के सहयोग से विद्यालय के लिए नए और भव्य भवन का निर्माण हुआ। पुराने सुथार पाड़ा स्थित विद्यालय को नए भवन में स्थानांतरित किया गया तथा विद्यालय का शैक्षणिक स्तर बढ़ाकर उच्च माध्यमिक किया गया। इसके साथ ही इसका नामकरण श्रीमती किशनी देवी मगनीराम मोहता राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में हुआ। इस प्रकार सुथार पाड़ा की गलियों से शुरू हुई बालिका शिक्षा की यात्रा एक नए और विस्तृत शैक्षिणक परिसर तक पहुंची। यह परिवर्तन केवल भवन का स्थानांतरण नहीं था, बल्कि जैसलमेर की बेटियों के लिए बेहतर शैक्षिणक सुविधाओं और उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

जैसलमेर के इतिहास में 1980 के दशक का मध्यकाल भीषण अकाल और विपरीत परिस्थितियों का दौर रहा। मरुभूमि के लोगों को उस समय राहत और सहयोग की आवश्यकता थी। तत्कालीन राज्यपाल वसंतदादा पाटिल, जिन्हें वसंतराव पाटिल के नाम से भी जाना जाता है, अपने राजस्थान कार्यकाल के दौरान जैसलमेर के आधिकारिक दौरे पर आए थे। इसी ऐतिहासिक संदर्भ में भामाशाह मगनीराम जी मोहता (गोयदानी माहेश्वरी) द्वारा राज्यपाल को सहयोग राशि की थैली भेंट किए जाने का प्रसंग जैसलमेर की जनकल्याणकारी परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

■ सुथारपाड़ा के पुराने विद्यालय से मोहता परिवार के सहयोग से बने भव्य भवन तक की गौरवगाथा, मरुभूमि में बेटियों की शिक्षा को मिली नई दिशा



यह प्रसंग उस समय के सामाजिक दायित्व, अकाल पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता और समाज के विकास में भामाशाहों की भूमिका को दर्शाता है। भामाशाह मगनीराम जी मोहता का नाम जैसलमेर में जनहित और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने वाले प्रतिष्ठित परिवारों की परंपरा के साथ सम्मानपूर्वक लिया जाता है।

मोहता परिवार के सहयोग से बालिका विद्यालय के लिए नए भवन का निर्माण इस बात का उदाहरण है कि समाज की वास्तविक उन्नित शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। विशेष रूप से उस समय बालिकाओं के लिए बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना दूरदर्शी और सामाजिक परिवर्तनकारी सोच का परिचायक था। गोयदानी माहेश्वरी परिवार की यह पहल अन्य भामाशाहों और प्रवासी नागरिकों के लिए भी प्रेरणा है कि अपनी मातृभूमि के विकास में योगदान देकर समाज की आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवारा जा सकता है। विद्यालय से जुड़ी एक और प्रेरणादायी परंपरा एक ग्राम सोने के मेडल के पुरस्कार की है। यह पुरस्कार केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि प्रतिभाशाली छात्राओं के सम्मान, प्रोत्साहन और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक बन चुका है। विद्यालय के वार्षिक उत्सव में जब किसी मेधावी छात्रा को शहर के गणमान्य नागरिकों, प्रशासनिक अधिकारियों और साथी छात्राओं की उपस्थिति में यह स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है, तो वह क्षण छात्रा और उसके परिवार के लिए गर्व और सम्मान का अवसर बन जाता है।

यह पुरस्कार बेटियों को यह विश्वास दिलाता है कि उनकी मेहनत, प्रतिभा और उपलब्धियों को समाज सम्मान देता है। दिल्ली जैसे महानगर में निवास करने के बावजूद अपनी जन्मभूमि जैसलमेर से जुड़ाव बनाए रखना और यहां की बेटियों की शिक्षा के लिए सहयोग करना भंवरलाल जी मेहता की सामाजिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विद्यालय के स्वर्ण पदक की परंपरा को बनाए रखने में उनका योगदान विशेष उल्लेखनीय है। महंगाई के कारण पुरस्कार की निर्धारित राशि कम पड़ने पर स्वयं अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवाकर उसकी गरिमा बनाए रखने का उनका संकल्प इस बात का उदाहरण है कि सच्चा दान केवल राशि देने तक सीमित नहीं, बल्कि किसी अच्छी परंपरा को निरंतर बनाए रखने में भी निहित है। यह भावना उन सभी प्रवासी नागरिकों और भामाशाहों के लिए प्रेरणादायी है, जो अप